सांध्य दैनिक

4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK

• वर्षः 11 • अंकः 168 पृष्ठः 8 • लखनऊ, बुधवार 23 जुलाई, 2025

मूल्य ₹ 3/-

चाहे जिन्दगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।

-स्टीफन हॉकिंग

भारत ने इंग्लैंड से वनडे सीरीज 2-1 से... 7 | 'सर' बढ़ा सकता है भाजपा का... 3 | वोट डालने से रोकना चाहती है... 2

सदन में फिर बढ़ी सरकार और विपक्ष में तकरार

सत्र का तीसरा दिन भी हंगामें की भेंट चढ़ा

» विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आए

» लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को लगाई फटकार

» नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी पर किया तीखा हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। हंगामे को बढ़ता देखकर राज्यसभा व लोकसभा को दो बजे तक स्थगित कर दी गई। बता दे बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर चर्चा की विपक्ष की मांग और लोकसभा व राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे पर राजनीतिक गतिरोध के बीच, सरकार ने आज के एजेंडे में छह विधेयक सूचीबद्ध किए हैं।

इन छह विधेयकों में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025, जिसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएँ व कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं। लेकिन संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरह की कोई बहस नहीं हो पा रही है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है।

ट्रंप कौन होते हैं सीजफायर कराने वाले, पीएम जवाब दें : राहुल

संसद में मानसून सत्र में हिस्सा लेकर बाहर निकले राहुल गांधी ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राहुल ने कहा- सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प बंद कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रम्प ने 25 बार बोला कि उन्होंने सीजफायर कराया। वो कौन होतें है बोलने वाला, ये उनका काम थोड़ी है। लेकिन पीएम ने इस पर एक जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। यह सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बयान कैसे दे सकते हैं? क्या वह कहेंगे कि संघर्ष विराम ट्रंप ने कराया? नहीं, वह ऐसा नहीं कहेंगे। यह हकीकत है कि ट्रंप ने संघर्ष विराम कराया है यह सिर्फ संघर्ष विराम की बात नहीं है, हम रक्षा उद्योग, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं।

'मोदी सरकार ने हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी'

किसी देश ने हमारी विदेश नीति का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दीं।

सत्तापक्ष पार्टी बनी चुनाव आयोग की प्रवक्ता : झा

उधर, दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि हमें जो कहना है, वो यहां कह रहे हैं और कोर्ट में भी कहेंगे। जब किसी पार्टी के इशारे पर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र लहूलुहान होगा, क्या सत्तापक्ष पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन गई है?

राज्यसभा में भी रार

वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को राज्यसभा की बैठक शुरु होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया। उच्च सदन की बैठक शुरु होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सूचित किया कि नियत कामकाज स्थगित कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उन्हें नियम 267 के तहत 25 नोटिस मिले हैं।

संसद के न चलने से सबसे ज्यादा फायदा सरकार को होता है : डेरेक ओब्रायन

विपक्ष के इस व्यवहार पर उठ रहे सवालों के बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने बुधवार को कहा कि जब संसद नहीं चलती है तो सबसे ज्यादा फायदा सरकार को होता है। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मानसून सत्र के दो दिन ''बेकार'' चले गए और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ओं'ब्रायन ने कहा, ''केंद्र सरकार ने संसद के दो दिन व्यर्थ गंवा दिए। जब संसद नहीं चलती है, तो फायदा किसे होता है? सत्ता में बैठी सरकार को। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है, संसद जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जब संसद काम नहीं करती है तो सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र का कुल समय 190 घंटे का है जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत सरकारी कामकाज के लिए है। ओं'ब्रायन ने कहा कि प्रश्नकाल के लगभग आधे प्रश्न और शून्यकाल के आधे नोटिस विपक्षी सांसदों द्वारा दायर किए जाते हैं, जिससे विपक्षी सदस्यों के पास सार्वजनिक महत्व के प्रश्न और मुद्दे उठाने के लिए कुल 31 घंटे का समय होता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को कुल 190 घंटों में से 135 घंटे सरकारी कामकाज और अन्य मुद्दों के लिए मिलते हैं जो उनके अनुसार कुल समय का लगभग 70 प्रतिशत है। उन्होंने सुझाव दिया, ''सरकार के लिए उपलब्ध घंटों में कटौती करना उचित है। विपक्ष को कुछ और समय दिया जाना चाहिए।

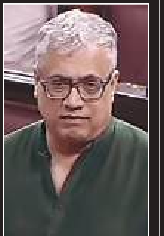

सड़कों का आचरण संसद में कर रहा है विपक्ष : बिरला

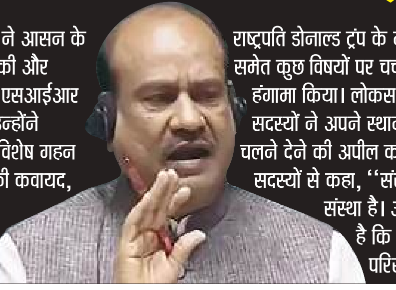

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने वाले सांसदों पर निर्णायक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बुधवार को नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि वे सड़कों का आचरण संसद के भीतर कर रहे हैं, जबकि वो 'माननीय' हैं और उनका व्यवहार 'माननीय' जैसा ही होना चाहिए। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन निचले सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी दलों के सदस्य पहले दो दिन की तरह ही हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं, जिन पर एसआईआर विरोधी नारे लिखे हुए थे। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों समेत कुछ विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों ने अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा, ''संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। आपसे मेरा आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर आपका व्यवहार, आचरण और कार्यपद्धति मर्यादित होनी चाहिए। देश की जनता ने आप लोगों को अपनी आवाज, कठिनाई, चुनौतियों, देश से जुड़ें मुद्दों और नीतियों पर चर्चा के लिए भेजा है।'' उन्होंने कहा, ''आप सड़कों का आचरण-व्यवहार संसद में कर रहे हैं। देश यह देख रहा है। आप जिन राजनीतिक दलों से हैं, उनके नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश उनके सदस्यों के आचरण और कार्यपद्धति को देख रहा है।''

वोट डालने से रोकना चाहती है बीजेपी : अखिलेश

» बोले सपा प्रमुख- आवाज उठाने वालों को ही थमा दी जाती है नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एकबार फिर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। सपा मुखिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती है। बिहार में जो कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में वोट डिलीट किए गए थे। जिन लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, उनमें से कई लोगों के वोट 2022 के चुनाव में डिलीट कर दिए गए थे।

अखिलेश यादव ने कहा है कि जब हमने आवाज उठाई तो चुनाव आयोग ने हमें नोटिस दिया था। समाजवादी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में मेहनत करके ऐसे 18 हजार से ज्यादा लोगों की पहचान की, जिन्होंने पहले वोट डाला था, लेकिन अगले चुनाव में उनका वोट डिलीट कर दिया गया था, उनके शपथ पत्र लेकर चुनाव आयोग को भेजा था। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

पहलगाम के मामले पर लोकसभा में हो चर्चा

अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि पहलगाम के मामले पर लोकसभा में चर्चा हो और जब चर्चा हो तो उस समय प्रधानमंत्री जी मौजूद रहें, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री जी के क्या चर्चा और क्या बयान। पहलगाम हमले के मामले में क्या भूल हुई, क्या चूक हुई और क्या गलती हुई। क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुई। इस तरह की घटना कोई एक बार नहीं हुई। पहलगाम में हुई, पुलवामा में भी हुई थी। भाजपा सरकार के समय में संसद भवन पर हमला भी हुआ था।

समाजवादी मजदूर सभा ने पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने की उठाई मांग

समाजवादी मजदूर सभा ने पैदल मार्च निकालकर पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने, स्कूलों का विलय रोकने की मांग उठाई और राज्यपाल को पांच सूत्री ज्ञापन भेजा। सभा के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू की अगुवाई में सपा के जिला मुख्यालय से निकला मार्च जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचकर संपन्न हुआ। ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि किसान, मजदूर, नौजवान दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर है। सरकार प्राथमिक विद्यालय बंद कर रही है और धार्मिक आयोजनों पर बजट लुटा रही है। उन्होंने मनरेगा मजदूरों को साल में 300 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान करने, नई श्रम संहिता को समाप्त करने की मांग की। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष जय सिंह जयंत, महासचिव शब्बीर अहमद खान, हरिशंकर यादव, मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव सुनील यादव, मनोज पाल, विनोद यादव, पूर्व प्रधान विनोद शुक्ला, अताउल्लाह खान आदि मौजूद रहे।

मेरे खिलाफ हो रहा पीआर एजेंसी का इस्तेमाल : भूपेश

» स्क्रीनशॉट शेयर कर कही अपनी बात

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। ईडी ने उनके भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार कर रायपुर के ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं।

इस बीच भूपेश बघेल का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट के जरिये उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम बघेल ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि कुछ लोग इतने बेचारे हैं कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखवाने के लिए, अब पीआर एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्वीट कहाँ रचे जा रहे हैं, कहाँ भेजे जा रहे हैं, कहाँ करवाए जा रहे हैं। सब कुछ घूमकर मुझ तक भी पहुँच रहा है। आप पहले से बेनक़ाब हैं, नक़ाब पहनने की कोशिश न कीजिए।

बीजेपी के दबाव में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिया इस्तीफा : बेनीवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कसा तंज, कहा- स्पष्ट करना चाहिए

जयपुर। नागौर सांसद और राष्ट्रपति लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने राज्यसभा के सत्र के बीच में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जो त्याग पत्र दिया है, वह दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दबाव का परिणाम है।

बेनीवाल ने कहा, अगर यह इस्तीफा वास्तव में स्वास्थ्य कारणों से होता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पुनर्विचार की सलाह जरूर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि वह एनडीए के विरोध में रहते हुए भी क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ के समर्थन में खड़े हुए थे और उन्हें वोट दिया था। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ ने कई मौकों पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उजागर कीं।

विधानमंडल का मानसून सत्र 11 अगस्त से

» इस सत्र में पेश होंगे कई महत्वपूर्ण अध्यादेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विधानमंडल का मानसून सत्र आगामी 11 अगस्त से शुरू होगा। कैबिनेट ने संसदीय कार्य विभाग द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि इससे पहले 18 फरवरी को विधानमंडल का सत्र आहूत किया गया था, जिसका सत्रावसान 12 मार्च को कर दिया गया था।

मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार कई अध्यादेशों को मंजूरी के लिए सदन में पेश कर सकती है। इसके अलावा अन्य विधायी कार्य भी संपन्न होंगे। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने विधानमंडल में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेने का वित्त विभाग का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। बता दें कि मानसून सत्र में सीएजी की सात रिपोर्ट (प्रतिवेदन) सदन के पटल पर रखी जाएंगी। ये प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगी- शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के उपयोग पर प्रतिवेदन,सरयू नहर परियोजना पर प्रतिवेदन,भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण,सीएजी का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन,राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, खनन और अवैध खनन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव।

बंगाल के नागरिकों की पहचान पर हो रहा है हमला : ममता

» एनआरसी नोटिस भेजने पर भड़कीं सीएम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि असम की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार बंगाल के वास्तविक नागरिकों को ''एनआरसी नोटिस'' भेज रही है। उन्होंने भाजपा पर बांग्ला पर हमला करने का भी आरोप लगाया।

बनर्जी ने अलीपुरद्वार जिले के एक निवासी और कूचबिहार के एक अन्य व्यक्ति को कथित तौर पर भेजे गए ऐसे नोटिस का उदाहरण दिया। सोमवार को यहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शहीद दिवस रैली में मुख्यमंत्री ने असम के अपने समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा की आलोचना की और बंगाल के निवासियों को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) नोटिस भेजने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया तथा मांग की कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में दखल देना बंद करें। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा, ''ऐसी कार्रवाइयां अस्वीकार्य हैं और बंगाल के निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।'' पिछले हफ्ते दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच तब वाकयुद्ध छिड़ गया, जब बनर्जी ने असम सरकार की कार्रवाइयों को बांग्ला भाषी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ''भाजपा का विभाजनकारी एजेंडा'' बताया। शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि वह ''सीमा पार से जारी, अनियंत्रित मुस्लिम घुसपैठ का निडरता से विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को बनर्जी ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार बांग्ला और राज्य के लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है तथा बांग्ला बोलने वालों को 'बांग्लादेशी नागरिक' करार देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कल भी अलीपुरद्वार के एक परिवार को असम सरकार से नोटिस मिले। असमिया में लिखे ये नोटिस कोकराझार स्थित विदेशी न्यायाधिकरण से आए थे। असम, बंगाल के मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? यह अनैतिक, असंवैधानिक और गैरकानूनी है। मैं भाजपा की 'डबल इंजन' वाली सरकार से कहूंगी कि वे अपने काम से काम रखें। शर्मा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री मणिपुर में हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सके।

रामनगर में विद्युत सब-स्टेशन का विधायक ने किया लोकार्पण

» एमएलए बोले- क्षेत्र के सभी गांव होंगे रोशन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जौनपुर। जनपद के रामनगर (नौरंगाबाद) में स्थानीय विधायक रमेश चन्द्र मिश्र ने 33/11 केवी क्षमता के विद्युत सब-स्टेशन का शुभारंभ किया। यह सब स्टेशन 7 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से न चले।

उन्होंने कहा कि इस विद्युत सब स्टेशन से करीब 25 गांवों को बिजली मिलेगी। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता रामदास, अधिशासी अभियंता प्रकाशदेव पांडेय, उपखंड अधिकारी

एसके सिंह, उपखण्ड अधिकारी सिविल श्वेता सिंह, ग्राम प्रधान अशोक सिंह, विधायक प्रतिनिधि गंगा प्रसाद सिंह, मंडल अध्यक्ष शनि शुक्ला, सिकंदर मौर्य, विनोद शर्मा, मृगेंद्र सिंह शिवबाबा, मिथिलेश सिंह, आरके उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

‘सर’ बढ़ा सकता है भाजपा का ‘सिर दर्द’

राजद-कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने भाजपा को घेरा

- » वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा
- » संसद व बिहार विस में विपक्ष ने उठाया मुद्दा
- » सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंचा मामला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर पर पक्ष-विपक्ष आमने सामने है और मामला मीडिया माध्यम से आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। यही नहीं संसद से लेकर बिहार विधान सभा तक यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यहीं नहीं इसको लेकर विपक्ष सदन से लेकर बाहर तक हंगामा मचा रहा है।

उधर राजद, कांग्रेस के साथ-साथ ओवैसी की पार्टी भी मुखर हो गई हैं। इसबीच चूकि बिहार में चुनाव होने में समय कम बचा है इसी को लेकर विपक्ष भाजपा व चुनाव आयोग पर बिफरा हुआ है उसको ऐसा लगता है कि इतने कम समय में करोड़ों मतदाताओं का पुनरीक्षण कैसे होगा। वहीं कोर्ट में मामला पहुंचने से भी विपक्ष राहत महसूस कर रहा है।उम्मीद है कि देर आयद, दुरुस्त आयद करते हुए न्यायालय ऐसे दिशा निर्देश जारी करेगा कि भविष्य में राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ से चलने वाले मतदाता सूची सम्बन्धी खेल पर पूर्ण विराम लग सके।

बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बवाल

बिहार में वोटर लिस्ट विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। 9 जुलाई को विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर पटना में जोरदार प्रदर्शन भी किया। हालांकि, अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है।10 जुलाई को सुनवाई

के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट से कहा कि अभी तक सभी याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए पक्ष स्पष्ट रूप से रख पाना मुश्किल हो रहा है।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वोटर लिस्ट रिविजन का प्रावधान कानून में मौजूद है और यह प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में या फिर पूरी लिस्ट को नए सिरे से तैयार करके भी हो सकती है।

चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए एसआईआर

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस सहित कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

चुनाव आयोग के पास कोई शक्ति नहीं : कपिल सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास इसमें कोई शक्ति नहीं है। वे कौन होते हैं यह कहने वाले कि हम नागरिक हैं या नहीं।उन्होंने कहा, ये वे लोग हैं जो नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं है और कुछ ऐसे भी हैं जो पंजीकृत हैं और जिन्हें केवल धारा 3 के तहत ही हटाया जा सकता है। इसलिए यह पूरी प्रक्रिया चौंकाने वाली है।कपिल सिब्बल ने कहा कि वे

कहते हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं को आप वोट नहीं दे सकते। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? जिम्मेदारी उन पर है, मुझपर नहीं। उनके पास यह कहने के लिए सबूत तो होना चाहिए कि मैं नागरिक नहीं हूं। सिब्बल के सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह देखना उनका अधिकार नहीं है कि योग्य वोट दें और अयोग्य वोट न दें। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि तो आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।

महत्वपूर्ण पहचान आधार को एसआईआर में खारिज करने पर सवाल

ऐसे में सुलगता सवाल है कि जिस आधार पर आप लोगों को सरकारी धनराशि से सहूलियत देते हैं, उसी महत्वपूर्ण पहचान आधार को आप एसआईआर में खारिज कैसे कर सकते हैं। आपके ऐसा करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जो संस्थागत लूट चल रही है, उसकी अब सोशल ऑडिट जरूरी है, क्योंकि इस मामले में पक्ष-विपक्ष सभी शामिल हैं। सच कहूं तो इससे भारत के उन मूल निवासियों को क्षति हो रही है जिनका देश की सरकार और संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए।

मतदाता के मताधिकार से वंचित होने से लोकतंत्र पर असर : अभिषेक मनु

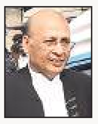

सुप्रीम कोर्ट में एक और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बात रखी और कहा कि यह नागरिकता का मामला है। उन्होंने कहा, एक मतदाता के मताधिकार से वंचित होने से लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। इसलिए हम कर रहे हैं कि अब तक हुए सभी 10 चुनाव गलत चुनावी आंकड़ों पर आधारित थे।

2003 को जारी वोटर लिस्ट वालों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं : चुनाव आयोग

विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी, 2003 को जारी की गई वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि वे सभी लोग संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्राथमिक तौर पर भारत के नागरिक माने जाएंगे। जिन लोगों के माता-पिता के नाम तब की मतदाता सूची में दर्ज है, उनको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज देने होंगे।

याचिकाकर्ताओं के वकील के सवाल

याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता नहीं दी जा रही है।उन्होंने कहा, जब देशभर में पहचान के सबसे विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर आधार और वोटर आईडी को माना जाता है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखना तर्कसंगत नहीं है। इससे पूरा सिस्टम मनमाना और भेदभावपूर्ण नजर आता है।

विपक्षी दलों के प्रमुख सवाल

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आपपी एक्ट में भी नागरिकता का प्रावधान है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको अगर यह करना है तो फिर इतनी देरी क्यों की। यह चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए। विपक्षी दलों और एडीआर की ओर से दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। इन याचिकाओं में 5 बड़े सवाल उठाए गए हैं।

पहला सवाल: सवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन
विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि चुनाव आयोग का यह फैसला जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के नियम 21A के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का भी उल्लंघन है।

दूसरा सवाल: नागरिकता, जन्म और निवास पर मनमानी
एक्टिविस्ट अरशद अजमल और रूपेश कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह प्रक्रिया नागरिकता, जन्म और निवास से संबंधित असंगत दस्तावेजीकरण लागू करने की मनमानी है।

तीसरा सवाल: लोकतांत्रिक सिद्धांत कमजोर करने वाला फैसला
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के फैसले को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाला बताया गया है।

चौथा सवाल: गरीबों पर असमान बोझ
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि चुनवा आयोग की यह प्रक्रिया गरीब, प्रवासी के साथ ही महिलाओं और हाशिए पर पड़े अन्य समूहों पर असमान बोझ डालने वाली है।

पांचवां सवाल: गलत समय पर शुरू की गई प्रक्रिया
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये प्रक्रिया गलत टाइम पर शुरू की गई है। मनोज झा ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में गलत समय पर शुरू की गई है, जिसकी वजह से करोड़ों वोटर मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर न केवल आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है, बल्कि ऐसा करने से इसकी प्रक्रि या भी ज्यादा आसान होगी और विभिन्न आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, किसी भी विदेशी व्यक्ति का नाम भी मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, अन्यथा मतदाता सूची की विश्वसनीयता सवालों के कठघरे में रहेगी। कोर्ट का सही मानना है कि ऐसे एसआईआर अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक

चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। जहां तक इसे लेकर संशय की स्थिति है तो आधार, राशन कार्ड या जॉब कार्ड को मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर रखने के कारण बड़ी आबादी के सामने संकट खड़ा हो गया है।

चुनाव आयोग पर भी कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता न देने को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है। आयोग के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होता। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे यो फिर ये बड़ी कसौटी होगी। यह गृह मंत्रालय का काम है, आप उसमें मत जाइए। उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है, फिर आपकी इस कवायद का कोई औचित्य नहीं रहेगा।

जिद... सच की

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

कांवड़ियों के साथ आमजन को भी न हो परेशानी

> “केंद्र और राज्य सरकारों को कांवडियों की सुविधा के साथ आम आदमी की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यवस्था की जानी चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान आम यातायात प्रभावित न हो। केंद्र एक्सप्रेस वे बना रहा है ताकि यातायात के किसी वाहन को परेशानी न हो। इसके लिए कांवड यात्रा वाले प्रदेश की सरकारों का केंद्र के साथ मिल बैठ कर प्लान करना चाहिए।

भारत में चूकि धर्मनिरपेक्षता का शासन है इसलिए सबकी आस्था का ख्याल रखना सरकारों का दायित्व है। हालांकि पिछले कुछ से बहुसंख्यक आबादी की आस्था में कट्टरता हावी होती दिखाई दी है। चाहे वो महाकुंभ हो या अन्य कोई धार्मिक आयोजन। अभी वर्तमान उत्तर भारत में सावन की शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है। कांवड़ यात्रा के कारण उत्तर भारत में यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे आम जन परेशान हो जाता है। भक्तों को ध्यान रखना चाहिए उनकी आस्था की वजह से किसी और को परेशानी न हो। हरिद्वार प्रशासन के अनुसार पिछले साल साढ़े चार करोड़ से ज्यादा शिवभक्त जल लेने हरिद्वार पंहुचे। 2023 में चार करोड़ श्रद्धालु आए थे। ये यात्रा अभी चल रही है, अनुमान है कि इस बार अकेले हरिद्वार से ही कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पांच करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, किंतु कुछ स्थानों पर पूरे सावन कांवड़ चढ़ती हैं। श्रद्धालु के समूह हरिद्वार आते और जल लेकर अपने गंत्व्यों की ओर रवाना होते रहते हैं।

उत्तर भारत की इस कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सरकार व्यापक व्यवस्थाएं करती हैं, किंतु यात्रा के समय ये सब व्यवस्थांए बौनी पड़ जाती हैं। इसी कारण कई जगह कांवड़ियों के हंगामा करने की सूचनाएं आती हैं। कुछ जगह तोड़फोड़ और आगजनी तक हो जाती है। इस सबका कारण यात्रा से कुछ पहले तैयारी करना है, जबकि इसके लिए पूरे साल तैयारी की जानी चाहिए। इसके लिए अलग से विभाग होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। केंद्र और राज्य सरकारों को कांवडियों की सुविधा के साथ आम आदमी की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यवस्था की जानी चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान आम यातायात प्रभावित न हो। केंद्र एक्सप्रेस वे बना रहा है ताकि यातायात के किसी वाहन को परेशानी न हो। इसके लिए कांवड यात्रा वाले प्रदेश की सरकारों का केंद्र के साथ मिल बैठ कर प्लान करना चाहिए। कावंड यात्रा वाले मार्ग पहले ही इस तरह बनाए जांए कि उसकी साइड से आम यातायात सुगमता से अनवरत चलता रहे। कांवड यात्रा वाले मार्ग पर कांवड़ यात्रियों के लिए पहले से ही दो अलग लेन बनाकर रखी जा सकती हैं। यात्रा के समय में इन पर कांवड़िए और उनके वाहन चलें, बाद में ये लेन आम ट्रैफिक के लिए प्रयोग हों। कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर कांवड़ यात्रियों के आराम रूकने के स्थान पहले से चिंहित हों। स्थान ऐसे हों कि यहीं कांवड़ शिविर भी लग सकें। साथ ही लोगों व भक्तों को भी अपना कर्तव्य जानना चाहिए अपने पूजा के लिए आम नागरिकों को परेशानी में नहीं डालना चाहिए।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

विकास की आकांक्षाओं के लिए परिवर्तन की बयार

सुषमा जुगरान ध्यानी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में इस बार माहौल कुछ अलग तरह का नजर आ रहा है। अब जनता लोकतंत्र की इस सबसे छोटी इकाई के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद पाल रही है और इसमें सामान्य ग्रामीण जन से लेकर बौद्धिक और शिक्षित वर्ग तक की महत्वपूर्ण सहभागिता दिख रही है। गौरतलब है कि इस बार गांवों में बड़ी संख्या में निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गये हैं। यही नहीं, उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य भी इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 20,820 ग्राम पंचायत सदस्यों समेत कुल 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गये हैं। इनमें 1361 ग्राम प्रधान, 240 क्षेत्र पंचायत सदस्य और आठ जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं।

हालांकि, पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों का निर्विरोध चुना जाना कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार उत्तराखंड से यह खबर इसलिए खासतौर पर सुर्खियों में है क्योंकि इन चुनावों में सरकारी सेवा से ससम्मान रिटायर होने वाले शिक्षक, प्रधानाचार्य और पुलिस व सेना के ऐसे वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं जिनका अब से पहले राजनीति से कोई लेना-देना नहीं रहा है और जो अपने पैतृक गांव लौटकर ग्राम प्रधान के रूप में उसके विकास का सपना मन में पाले हुए हैं। परिवर्तन की यह बयार गढ़वाल क्षेत्र के सुदूर उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी से लेकर कुमाऊं के चंपावत और पिथौरागढ़ तक बह रही है। रिवर्स पलायन की इससे बड़ी नजीर भला और क्या हो सकती है! निर्विरोध चुने गये 1361 ग्राम प्रधानों में सबसे ज्यादा खबरों में दो नाम ऐसे हैं जो सेना और पुलिस विभाग में बहुत ही ऊंचे पद से रिटायर होने के बाद अपने सुविधाहीन गांवों में लौट आये हैं जबकि ये भी दिल्ली, देहरादून या किसी सुविधा-संपन्न महानगर में आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे। रिवर्स पलायन के विचार को व्यावहारिक धरातल पर उतारते हुए अपने गांव में बसने का निर्णय ले अब ये गांव वालों की आम सहमति से ग्राम प्रधान बन विकास के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। इनमें पहला नाम है सेना से रिटायर हुए कर्नल यशपाल नेगी का।

पौड़ी जिले के बीरोंखाल ब्लाक के वीरगणा गांव के मूल निवासी कर्नल यशपाल नेगी रिटायर होने के बाद अपने गांव लौटने के लिए कृत संकल्प थे। 2020 में जब वह सपत्नीक गांव लौट अपने बंजर पड़े खेतों को आबाद करने

की मंशा से खेती-किसानी में जुट गये तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। आज कर्नल अपने लहलहाते खेतों के साथ जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके इस काम में उनकी पत्नी उनसे भी ज्यादा उत्साहित दिखती हैं। कर्नल यशपाल और उनकी पत्नी नि:स्वार्थ भाव से गांव के बच्चों को शिक्षा और स्वरोजगार के प्रति भी प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नाम है पूर्व आईपीएस विमला गुंज्याल, जो पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित व्यास घाटी के गुंजी गांव की मूल निवासी हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक 35 सालों के स्वर्णिम सेवाकाल के बाद पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर होने वाली विमला जी भी अब अपने पैतृक गांव गुंजी में रह रही हैं। गुंजी के ग्रामीणों की इच्छा पर उनके ग्राम प्रधान पद के लिए हामी भरने के बाद सभी दावेदारों ने अपने नाम वापस ले लिए और उन्हें निर्विरोध प्रधान चुन लिया। ऐसे ही टिहरी के अमिल्डा गांव ने अवकाशप्राप्त प्रधानाचार्य दिनेश डंगवाल को निर्विरोध अपना प्रधान चुना है। इनके अलावा भी ऐसे बहुत से शिक्षित और जागरूक ग्रामीण निर्विरोध प्रधान चुने गये हैं जिनका अब से पहले राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन अपने गांव के विकास के लिए उनके मन में भरपूर जज्बा है। प्रबुद्ध या ईमानदार प्रतिनिधि को निर्विरोध चुनने संबंधी उत्तराखंड के जनमानस का यह हृदय परिवर्तन इसलिए उम्मीद जगा रहा है क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के तहत जब से ग्राम प्रधानों को मानदेय के साथ ग्रामसभा के लिए निर्धारित फंड के वित्तीय अधिकार मिले हैं तब से एक अदद ग्राम प्रधानी के लिए भी साम-दाम-दंड-भेद की नीति के तहत आम चुनाव की तरह ही सिर फुटौवल मची दिखती है जो इस बार भी है ही, लेकिन कई ग्राम और क्षेत्र पंचायतों की तस्वीर बदली भी हुई है जो उत्तराखंड के सुखद भविष्य के लिए आशा की एक छोटी-सी किरण बनती दिख रही है।

इस सकारात्मक पहल का सबसे तात्कालिक लाभ तो यही है कि चुनाव जीतने के लिए पैसों की बंदरबांट और मुर्गा ब शराब-पार्टियों का जो घिनौना रूप दिखता है, उससे वातावरण विषाक्त होने से बच जाता है। उत्तराखंड के लोग इस बात को तो बखूबी समझते रहे हैं कि राज्य निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का विकास था लेकिन राज्य गठन से लेकर आज तक बारी-बारी से दो राष्ट्रीय दलों- भाजपा और कांग्रेस के हाथों सत्ता सौंपकर देहरादून में बैठकर अलग उत्तराखंड के उद्देश्य को कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रहित में नहीं भाषाई अस्मिता की जंग

विश्वनाथ सचदेव

पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले एडवोकेट उज्ज्वल निकम को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। निकम के अनुसार यह सूचना उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन पर संपर्क करके दी थी। प्रधानमंत्री ने फोन पर एडवोकेट निकम से कहा था, ‘मी मराठी बोलूं का हिंदी?’ इस पर निकम कुछ हंस दिये, पर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंसे थे। वैसे प्रधानमंत्री का मराठी में बोलना और निकम एवं मोदी जी का हंसना स्वाभाविक-सी बात है, पर हाल के दिनों में महाराष्ट्र में भाषा की जो राजनीति चल रही है उसे देखते हुए यह प्रकरण सामान्य से थोड़ा हटकर लग रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा निकम के साथ मराठी में बोलने वाली यह बात जिस दिन अखबार में छपी, उस दिन एक अन्य समाचार भी अखबार के पहले पृष्ठ पर छपा था।

यह समाचार मुंबई के उपनगर विरार का था, जहां उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक रिक्शा वाले की इसलिए पिटाई कर दी कि वह मराठी में नहीं बोल पा रहा था- हिंदी में बोल रहा था। रिक्शा चालक उत्तर प्रदेश का था और शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मानना था कि उसे अपनी कर्मभूमि की भाषा मराठी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी न बोल पाना मराठी भाषा का अपमान कैसे हो गया, पता नहीं, पर प्रधानमंत्री द्वारा एडवोकेट निकम से मराठी में बोलना यह संकेत तो दे ही रहा है कि राज्य में भाषा को लेकर फिर से उठा यह विवाद अप्रिय स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। महाराष्ट्र में आकर जीविका कमाने वाले को राज्य की भाषा आनी चाहिए, इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सच बात तो यह है कि एक से अधिक भारतीय भाषाएं जानने वाले भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वह बहुभाषी है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं है, भाषा हमारी अस्मिता है, पहचान है। हमारे संविधान में हिंदी को देश की राजभाषा का स्थान दिया गया है, लेकिन संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित की गयी सभी बाईस भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं।

सब पर हमें गर्व है। इनमें से किसी एक का भी अपमान समूची भारतीयता का अपमान है। अर्थात् स्वयं अपना अपमान। कोई क्यों करना चाहेगा भला अपना अपमान? सच तो यह है कि अपनी भाषाई विविधता पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाग्यशाली हैं हम कि हमारे पास भाषाओं का इतना बड़ा खजाना है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि यह अहसास हम सब में जगे। लेकिन यह भी एक पीड़ादायक सच्चाई है कि अक्सर भाषा को राजनीति का हथियार बनाया जाता है। महाराष्ट्र में इन दिनों चल रहे भाषाई-विवाद के पीछे भी कुछ ऐसी ही राजनीति है। कुछ अरसा पहले महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा-नीति में परिवर्तन संबंधी शासनादेश जारी किया था, जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि प्राथमिक कक्षाओं में तीन भाषाएं पढ़ाई जाएं- मातृभाषा यानी मराठी, अंग्रेजी और हिंदी। मनसे को यह राजनीतिक स्वार्थ साधने का अवसर दिखा। उसने इसे हिंदी-मराठी का विवाद बना दिया और तरीका वही अपनाया जो बीस साल पहले आजमाया जा चुका था- यानी मराठी माणूस और मराठी अस्मिता की बात।

साथ ही जोर-जबरदस्ती वाली नीति। उद्धव ठाकरे को भी इसमें अवसर दिख गया। मराठी के अपमान का नारा लगाकर राजनीति सधने लगी। राजनीतिक स्वार्थ का ही तकाजा था कि महाराष्ट्र सरकार को भी तीन भाषाओं वाला शासनादेश वापस लेना पड़ा। अब एक समिति बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पर मुद्दे की आंच ठंडी नहीं हुई। उज्ज्वल निकम से प्रधानमंत्री का हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा गया भाषा वाला सवाल और विरार में रिक्शा चालक की पिटाई वाला प्रकरण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाषाई-विवाद वाली राजनीति की आंच अभी सुलग रही है और इसे अभी और सुलगाया जायेगा। ‘मनसे’ और ‘उबाठा’ की कोशिश रहेगी कि मुंबई महानगरपालिका समेत राज्य में नगर निकायों के चुनाव तक यह आंच सुलगती रहे, ताकि उनकी राजनीति की रोटियां सिकती रहें। पहले भी समय-समय पर स्थानीय और पर प्रांतियों का मुद्दा राजनीति का हथियार बनता रहा है, अब भी बनेगा। इसका किसको कितना लाभ मिलेगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा, पर भाषाई अस्मिता और प्रांतीयता के नाम पर लड़ी जा रही यह लड़ाई किसी भी दृष्टि से राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं कहीं जा सकती।

महाराष्ट्र की राजनीति में अपना स्थान खोजती ‘मनसे’ और अपना खोया स्थान फिर से प्राप्त करने की कोशिश में लगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस ताजा विवाद के सहारे जुड़ने का मौका भले ही मिल गया हो, पर राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भाषाई अस्मिता के नाम पर लड़ी जा रही इस लड़ाई का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि यह राजनीति और भाषा के नाम पर लड़ी जाने वाली लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो रही है। देश के अन्य राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, असम आदि में भी इस तरह की विभाजनकारी प्रवृत्तियां समय-समय पर सिर उठाती रही हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने की इस राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति से उबरें। यह राष्ट्र हम सब का है। हम यानी हम सब भारतीयों का। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी जाने-बसने का अधिकार देता है। भाषा, धर्म, जाति आदि के नाम पर देश के किसी भी नागरिक से उसके वे अधिकार छीनने की कोशिश स्वीकार्य नहीं हो सकती जो संविधान ने उसे दिये हैं।

तरबूज के छिलकों से चमक उठेगा आपका चेहरा

ऐसे करें प्रयोग

इसके प्रयोग के लिए तरबूज के हरे छिलके को छीलकर उसका सफेद हिस्सा निकाल लें। अब इसे अपनी स्किन पर अच्छी तरह से रगड़ें। 10 मिनट इस छिलके को चेहरे पर रगड़ने के बाद सूखने दें और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इससे आपके चेहरे की कई परेशानियां कम होंगी। ये टोनर स्किन टोन को इवन करता है, जिससे चेहरा एक समान दिखता है।

बना सकते हैं फेस पैक

वैसे तो बाजार में हर स्किन टाइप के हिसाब से फेस पैक मिलते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो तरबूज के छिलकों से भी फेस पैक बना सकते हैं। इसके लिए 2 टेबलस्पून तरबूज का सफेद छिलका, जिसे आप कद्दूकस कर सकते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून बेसन या मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिलाकर मिक्स करें। तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे चेहरे पर अप्लाई करें। 20 मिनट के लिए इस मास्क को ऐसे ही लगा रहने दें और फिर चेहरे को धो लें। इसके इस्तेमाल से भी आपका चेहरा खिल उठेगा।

झुर्रियों से दिला सकता है छुटकारा

तरबूज के छिलके का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन की झुर्रियां कम हो सकती हैं। दरअसल, इसमें फ्लेवोनोइड, लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर रूप से मौजूद होता है। यह आपकी स्किन से फ्री रेडिकल्स के प्रभावों को कम करता है। ऐसे में इसके इस्तेमाल से आपके स्किन की झुर्रियां कम हो सकती हैं।

दाग-धब्बों से छुटकारा

स्किन पर तरबूज के छिलके को रगड़ने से स्किन पर मौजूद दाग-धब्बे कम हो सकते हैं। दरअसल, तरबूज के छिलके में मौजूद गुण स्किन को हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। साथ ही यह स्किन सेल्स को डैमेज होने से रोक सकते हैं। नियमित रूप से स्किन पर तरबूज के छिलके को रगड़ने से फ्री रेडिकल्स को बेअसर किया जा सकता है। साथ ही यह आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकता है।

स्क्रब भी बना सकते हैं

आप चाहें तो तरबूज के छिलके को स्क्रब की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए तरबूज के सफेद हिस्से का पेस्ट, थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है। तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट के बाद चेहरे को गीला करके मसाज करें। हल्के हाथ से मसाज करने के बाद आपका चेहरा खिल उठेगा। इससे चेहरे की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। इस स्क्रब के इस्तेमाल से टैनिंग हटती है और स्किन साफ होती है।

स्किन को करें फ्रेश

स्किन को फ्रेश और तरोताजा दिखाने के लिए भी आप नियमित रूप से तरबूज के छिलके को स्किन पर रगड़ सकते हैं। इससे आपकी स्किन की कायाकल्प बेहतर होती है। साथ ही गर्मियों के दिनों में स्किन पर होने वाली रेडनेस और जलन को भी कम कर सकता है। नियमित रूप से तरबूज को स्किन पर रगड़ने से आपकी स्किन जवां और खूबसूरत हो सकती है। इसके अलावा तरबूज के छिलके को नियमित रूप से चेहरे पर रगड़ने से आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग होती है। दरअसल, तरबूज के छिलके में प्राकृतिक टोनर होता है, जो आपकी स्किन से ऑयल को साफ करता है।

तरबूज और खरबूजा के सेवन से शरीर को गर्मी से राहत मिलती है। खासतौर पर तरबूज। इससे तो लोग तमाम तरह के पकवान बनाकर उसका सेवन करते हैं। हर कोई तरबूज का सेवन करना पसंद करता है। तरबूज स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद है। इसके सेवन से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। वहीं, गर्मियों में तरबूज खाने से आप फ्रेश और हाइड्रेट रहते हैं। लेकिन तरबूज खाकर हम सभी उसके छिलके फेंक देते हैं, पर इसके छिलके आपकी त्वचा को दमकाते हैं। तो तरबूज के छिलके का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप भी लगभग फ्री में अपना चेहरा चमका सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि टोनर स्प्रे वाला ही हो। तरबूज के छिलके को भी टोनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

हंसना मना है

शादी हमेशा अच्छा खाना पकाने वाली से करना चाहिए... क्योंकि... शादी के बाद प्यार कम हो सकता है, भूख नहीं...

पप्पू - स्वामी जी, यहां पहाड़ के ऊपर बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपकी खुशी का राज क्या है...
स्वामी जी - 21 वर्ष की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं! वैसे तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या ग्रीन टी... पप्पू - जी ग्रीन टी...
स्वामी जी - तपस्या, दो कप ग्रीन टी लाना... पप्पू बेहोश...

पत्नी ने पति से प्लाजो दिलाने की जिद की... पति ने तुरन्त पिताजी का 36 इंच मोहरी का पायजामा रंगवा कर दे दिया...! पत्नी खुशी जाहिर करते हुए नहीं थक रही... पिताजी पाजामा ढूंढते नहीं थक रहे... और...पति एक कोने में बैठकर हंसते -हंसते नहीं थक रहा...!!!

मरीज - डॉक्टर, मैं खाना न खाऊं, तो मुझे भूख लग जाती है, ज्यादा काम करता हूं तो थक जाता हूं, देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूं... डॉक्टर - रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे...

कहानी — ऊंट की गर्दन

बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत खुश रहते थे। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। काफी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे कि उन्हें वहां एक ऊंट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया। बीरबल ने झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊंट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से इसकी गर्दन ऐसी ही है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है, उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा, मेरी गर्दन ऊंट की तरह तो नहीं हो जाएगी न? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिया।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

घर-बाहर सुख-शांति बने रहेंगे। जीवनसाथी पर आपसी मेहरबानी रहेगी। जल्दबाजी में धनहानि हो सकती है। व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में सुकून रहेगा।

तुला

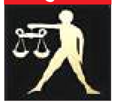

भाग्य का साथ मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। प्रमाद न करें।

वृषभ

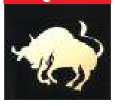

व्यवसाय ठीक-ठीक चलेगा। स्थायी संपत्ति की खरीद-फरोख्त से बड़ा लाभ हो सकता है। पार्टनरों का सहयोग समय पर मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

आय में निश्चितता रहेगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। व्यवस्था नहीं होने से परेशानी रहेगी। व्यवसाय में कमी होगी। नौकरी में नोकझोंक हो सकती है।

मिथुन

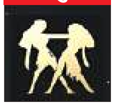

मित्रों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। पार्टी व पिकनिक की योजना बनेगी। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे।

धनु

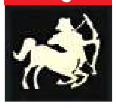

बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा हो सकती है। लेन-देन में सावधानी रखें। बगैर मांगे किसी को सलाह न दें।

कर्क

व्यवसाय से संतुष्टि नहीं रहेगी। आय में कमी तथा नौकरी में कार्यभार रहेगा। बेवजह लोगों से कहासुनी हो सकती है। दु:खद समाचार मिलने से नकारात्मकता बढ़ेगी।

मकर

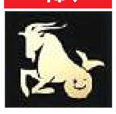

निवेश शुभ रहेगा। घर-बाहर सहयोग व प्रसन्नता में वृद्धि होगी। नई योजना बनेगी। सामाजिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। सुख के साधन जुटेंगे।

सिंह

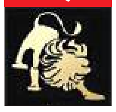

मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। कर्ज में कमी होगी। संतुष्टि रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार मनोनुकूल चलेगा। अपना प्रभाव बढ़ा पाएंगे। नौकरी में अनुकूलता रहेगी।

कुम्भ

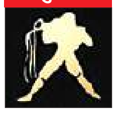

मित्र व संबंधी सहायता करेंगे। आय बनी रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। स्वास्थ्य पर खर्च होगा। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें। दूसरे के काम में दखल न दें।

कन्या

लाभ के अवसर हाथ आएंगे। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। व्यवसाय में जल्दबाजी से काम न करें। चोट व दुर्घटना से बचें।

मीन

लाभ के अवसर हाथ आएंगे। प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। मातहतों का सहयोग मिलेगा। पूजा-पाठ व सत्संग में मन लगेगा। आत्मशांति रहेगी।

राजा मर्डर केस पर क्राइम थ्रिलर फिल्म बनाएंगे आमिर खान!

आमिर खान ने फिल्म सितारे जमीन पर के जरिए जबर्दस्त सफलता हासिल की है। अब वे अपने अगले प्रोजेक्ट्स की तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिनेता अब मेघालय मर्डर केस पर क्राइम थ्रिलर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अभिनेता फिल्म बनाने की तैयारी में हैं।

मीडिया रिपोर्ट में अभिनेता के एक करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया है, आमिर खान मेघालय हत्याकांड की अपडेट पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने निजी रूप से इस केस पर नजर रखी है और अपने करीबी लोगों के साथ इस पर चर्चा की है। हो सकता है कि उनके प्रोडक्शन की तरफ से भी इस विषय पर कोई डेवलपमेंट हो।

जूम की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आमिर खान रियल लाइफ ट्रेजडी पर आधारित एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म बनाने के इच्छुक हैं। बता दें कि आमिर खान को सिनेमा की दुनिया में परफेक्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी हालिया रिलीज फिल्म सितारे जमीन पर के बाद अगली फिल्म का एलान नहीं किया है। हालांकि, खबरों के अनुसार मेघालय मामले ने उनका ध्यान खींचा होगा, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि उन्होंने सिर्फ फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया है या इसमें अभिनय भी करेंगे।

आमिर खान का अगला प्रोजेक्ट चाहे जो भी हो, यह अभी शुरुआती स्टेज पर है। अभी तक किसी की कास्टिंग नहीं हुई है। बता दें कि मेघालय मर्डर केस इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी से जुड़ा है। इंदौर के राजा और सोनम की शादी इस साल 11 मई को हुई। 20 मई को वे हनीमून पर गए। तीन दिन बाद कपल शिलांग से 65 किलोमीटर दूर सोहरा के पास लापता हो गया। पुलिस ने बताया कि 02 जून को राजा का क्षत-विक्षत शव चेरापूंजी में वेइसाडोंग फॉल्स के पास 200 फीट गहरी खाई से बरामद हुआ। हफ्तेभर बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने कथित तौर पर अपने पति की हत्या की बात कबूल की। सोनम ने कुशवाहा तथा तीन हत्यारों- विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत के साथ इस मर्डर की साजिश रची। चारों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

सुष्मिता सेन को डायमंड गिफ्ट करना चाहते हैं एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल

सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल ने साल 2021 में ब्रेकअप कर लिया था। सुष्मिता सेन और रोहमन अलग हो चुके हैं। मगर दोमों की केमिस्ट्री अभी भी बहुत ही बढ़िया है। दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं। रोहमन और सुष्मिता ने ब्रेकअप पर चुप्पी साधी हुई थी लेकिन फिर भी रेड कर्पेट, फैमिली फंक्शन में साथ में नजर आते हैं। हाल ही में रोहमन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो सुष्मिता को एक डायमंड गिफ्ट किया है।

रोहमन ने हाल ही में इंटेट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में सुष्मिता सेन के बारे में बात की। रोहमन से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने सुष्मिता सेन को कभी डायमंड गिफ्ट दिया है। रोहमन ने इस सवाल का बहुत ही मजेदार जवाब दिया है।

रोहमन ने दिया ये जवाब

रोहमन ने हंसते हुए कहा- जिस हिसाब के उनको डायमंड पसंद है, अभी मेरी औकात नहीं है इतना बड़ा खरीदने की। तो जिस दिन उस लायक बंनूगा, इंशाल्लाह जरुर। रोहमन यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सुष्मिता को किस तरह का डायमंड पसंद है। रोहमन ने कहा- उनका एक पसंदीदा डायमंड है, वो 22 कैरट का है। तो वो कमाने के लिए बहुक वक्त है। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी।

बता दें सुष्मिता और रोहमन ने साल 2018 में डेटिंग शुरू की थी। उनका रिश्ता तीन साल चला था। दोनों साल दिसंबर 2021 में अलग हो गए थे। अलग होने के बाद दोनों ने छुपाने की बजाय सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी थी। सुष्मिता ने लिखा था- हम दोस्त बनकर शुरू हुए थे, दोस्त ही रहेंगे... रिश्ता पहले खत्म हो गया था लेकिन प्यार हमेशा रहेगा।

सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल की हाल ही में एक वीडियो आई थी जिसमें रोहमन उनकी फोटो क्लिक करते हुए नजर आए थे। सुष्मिता और रोहमन का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था।

बॉलीवुड | मन की बात

ट्रोलर्स को दिव्यांका त्रिपाठी ने दिया करारा जवाब

टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने सभी ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। जी हां हाल ही में दिव्यांका कुकिंग शो लाफ्टर शेफ्स 2 में नजर आईं, जहां उनकी मुलाकात यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव से हुई। लेकिन जैसे ही दिव्यांका ने एल्विश को कोई और कलाकार समझ लिया और उनका नाम भी समर्थ लिया तो एल्विश के फैंस नाराज हो गए। इसके बाद एल्विश के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिव्यांका ने जिस समझदारी से जवाब दिया, उसने सभी का दिल जीत लिया। अभिनेत्री ने न सिर्फ ट्रोल्स को शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दिया, बल्कि उन्होंने एल्विश यादव के सच्चे फैंस को धन्यवाद भी कहा। दिव्यांका ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो लोग अच्छे व्यवहार से पेश आए, वो सच्चे फैन कहलाने लायक हैं। उन्होंने ट्रोल करने वालों को भी चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी वजह से उनकी सोशल मीडिया पर इंगेजमेंट काफी बढ़ गई है। दिव्यांका का ये अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आया। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सूझबूझ और विनम्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे। एक यूजर ने लिखा, दिव्यंका जैसी ग्रेसफुल एक्ट्रेस ही इस तरह का पॉजिटिव जवाब दे सकती हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा, ट्रोलर्स को प्यार से जवाब देना ही असली जीत है। पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब दिव्यांका शो के सेट पर एल्विश यादव को पहचानने में चूक गईं। उन्होंने उन्हें अभिनेता समर्थ जुरेल समझ लिया और 'हैलो समर्थ' कहकर पुकारा। इस पर सेट पर मौजूद कलाकार अभिषेक कुमार, अली गोनी और कृष्णा अभिषेक खूब हंसे और एल्विश ने भी मुस्कराते हुए दिव्यांका को अपना नाम बताया। जब दिव्यांका को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत माफी मांगी और मजाक में कहा कि एल्विश के फैंस उन्हें मार ही डालेंगे।

अनोखी अदालत, जहां भगवान के खिलाफ ही चलता है केस

हमारे देश में अलग अलग जगहों पर कई तरह की परंपराएं और रीति रिवाज निभाए जाते हैं। कई परंपराएं तो इतनी विचित्र और अनोखी होती हैं कि इनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही विचित्र परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस परंपरा के बारे में जानकर आपको अक्षय कुमार की फिल्म 'ओ माय गॉड' याद आ जाएगी। आपने अदालत में केस चलते हुए देखा होगा। लोग एक दूसरे पर मुकदमें कर देते हैं और कोर्ट में उस केस का फैसला होता है। लेकिन क्या आप ऐसी अदालत के बारे में जानते हैं, जहां भगवान और देवताओं पर ही केस चलता है। जानते हैं कि इस अनोखी अदालत के बारे में। यह अनोखी अदालत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लगती है। इस अदालत में देवताओं पर ही केस चलता है। इतना ही नहीं दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा तक सुना दी जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कंगारू कोर्ट के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इस अदालत में सारे माओवादी इक्ठ्ठा होते हैं। मगर बस्तर जिले में ही एक और अदालत लगती है। साल में एक बार लगने वाली इस अदालत में भगवान के खिलाफ मुकदमा चलता है। बस्तर में आदिवासी आबादी 70 प्रतिशत है। यहां गोंड, मारिया, भतरा, हल्बा और धुरवा जैसी जनजातियां रहती हैं। बस्तर में भंगाराम देवी का मंदिर है। यहां हर साल मानसून के दौरान भंगाराम मंदिर में भादो जात्रा उत्सव मनाया जाता है। इसी महोत्सव के दौरान जन अदालत लगाई जाती है। भंगाराम देवी मंदिर में तीन दिवसीय भादो जात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान भंगाराम देवी सभी मुकदमों की अध्यक्षता करती हैं। महोत्सव के दौरान लोग भगवान पर आरोप लगाते हैं। खास बात यह है कि इन मुकदमों में गवाही मुर्गियां और अन्य पशु-पक्षी देते हैं। फसल खराब होने से लेकर बीमारी तक इस अदालत में भगवान के खिलाफ सभी तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। सुनवाई के दौरान अगर भगवान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा भी मिलती है। सजा के तौर पर भगवान की मूर्तियों को एक निश्चित समय के लिए मंदिर के पीछे रख दिया जाता है। कई बार यह सजा आजीवन कारावास की भी होती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में जब तक भगवान अपनी गलती सुधार नहीं लेते, तब तक उन्हें मंदिर के पीछे रखा जाता है। वहीं शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान होने के बाद भगवान को फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इस महोत्सव में 240 गांवों के लोग हिस्सा लेते हैं। मुकदमे के बाद सभी के लिए महाभोज का भी आयोजन किया जाता है।

अजब-गजब | यहां कई भाईयों की होती है एक ही पत्नी

2 भाईयों ने की एक ही लड़की से शादी

इन दिनों एक शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश में दो सगे भाईयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली। यह घटना हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार का हाटी क्षेत्र की है। दोनों भाइयों ने एक दुल्हन के साथ एक ही मंडप में सात फेरे लिए। शादी तीनों की रजामंदी से हुई है। शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पांडव कालीन परंपरा की आम लोगों में चर्चा हो रही है। हिमाचल के सिरमौर, किन्नौर और उत्तराखंड के जौंसार बावर जैसे क्षेत्रों में बहुपति प्रथा रही है।

दुनिया में कई जगहें ऐसी भी हैं, जहां बहुपतित्व की प्रथा भी है। हालांकि इसके पीछे अलग अलग कारण हैं। वैसे तो हमारे समाज में बहुपतित्व की प्रथा को सही नजरों से नहीं देखा जाता लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है, जहां बहुपतित्व को बुरा नहीं माना जाता। यहां कई भाईयों की एक ही पत्नी होती है और यहां एक पत्नी कई पतियों के साथ एक ही घर में रहती है। यह बहुपतित्व की प्रथा तिब्बत में है।

बहुपतित्व एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं। तिब्बती समाज में यह प्रथा विशेष रूप से फ्रेटर्नल पॉलियंड्री के रूप में प्रचलित रही है, जिसमें एक ही परिवार के कई भाई एक ही महिला से विवाह करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार की संपति और संसाधनों को विभाजित होने से बचाना है।

तिब्बत, अपने अनूठे भूगोल, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां की परंपराओं में से एक प्रमुख प्रथा है बहुपतित्व, जो विशिष्ट रूप से तिब्बती समाज का हिस्सा रही है। यह प्रथा न केवल सामाजिक संरचना को समझने में मदद करती है, बल्कि तिब्बती समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक जड़ों को भी उजागर करती है। तिब्बत के कठोर भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण कृषि और पशुपालन जैसे संसाधनों पर निर्भरता रही है। जमीन का सीमित और उपजाऊ भाग होने के कारण परिवारों को इसे बंटवारा होने से बचाने के लिए बहुपतित्व प्रथा को अपनाना पड़ा। एक महिला से शादी करने वाले भाइयों का संयुक्त परिवार एक ही संपति पर निर्भर रहता है। इससे जमीन और संपति बंटती नहीं है और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होता है। तिब्बती समाज में परिवारों का एकजुट रहना और सामुहिक सहयोग की भावना प्रमुख है। यह प्रथा इन मूल्यों को बनाए रखने में सहायक रही है।

तिब्बत में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में भिन्नता के कारण भी यह प्रथा अस्तित्व में आई। बहुपतित्व के कारण परिवारों में झगड़ों और विवादों की संभावना कम होती है, क्योंकि सभी भाई एक ही महिला से जुड़े होते हैं। इस प्रथा में महिलाओं को परिवार की धुरी माना जाता है। वे परिवार के सभी सदस्यों को साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहुपतित्व प्रथा में बच्चे पूरे परिवार की संयुक्त जिम्मेदारी माने जाते हैं, जिससे उनकी परवरिश में सामूहिक योगदान होता है। हालांकि आधुनिकीकरण और सामाजिक बदलाव के कारण तिब्बत में बहुपतित्व प्रथा धीरे-धीरे कम हो रही है। इसके अलावा चीन सरकार, जो तिब्बत पर प्रशासनिक अधिकार रखती है, ने बहुपतित्व को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी है।

तिब्बती युवा अब शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। इससे पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव हो रहा है। आधुनिक विचारधाराओं के कारण महिलाएं अब अपनी इच्छाओं और अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हो रही हैं, जिससे प्रथा का पालन कम हो रहा है।

तीन महीने में ही भाजपा सरकार नाकाम : हारुन

कांग्रेस ने आप पर भी साधा निशाना

» पूर्व मंत्री बोले- सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें सीएम रेखा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री हारुन यूसुफ ने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी और वर्तमान भाजपा सरकार दिल्ली की बढ़ती आबादी की जरूरतों के अनुसार परिवहन सुविधा मुहैया कराने में विफल रही है। यूसुफ ने कहा, जहां दिल्ली को 12-14 हजार बसों की जरूरत है, वहां भाजपा सरकार ने पिछले छह महीनों में केवल 400 छोटी इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी हैं, जबकि पिछले डेढ़ वर्ष में 2400 बसें सेवा से बाहर हो चुकी हैं और मार्च 2026 तक 1700 और हटाई जानी हैं। उन्होंने बताया, 2012-13 में प्रतिदिन डीटीसी बसों में 46.77 लाख लोग सफर करते थे, जो 2023-24 में घटकर 25 लाख रह गए। यूसुफ ने कहा कि 2022 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, डीटीसी घाटा 60,750 करोड़ रुपये था, जो 2025 में 65,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने मांग की है कि भाजपा सरकार डीटीसी का कर्ज माफ कर इसे पुन: सशक्त बनाए, जैसे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई बार किया गया था। वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. ओनिका मेहरोत्रा ने कहा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को खत्म करने की योजना के तहत सहेली कार्ड के नाम पर आधार और दस्तावेज मांगना अनुचित है। उन्होंने पिंक बसों की मांग की। इससे पहले आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि भाजपा के पास एक ही तरीका है कि योजना में भ्रष्टाचार हो रहा था इसलिए बंद कर रहे हैं। अब वह डीटीसी बसों में गरीब महिलाओं को दी जाने वाले पिंक टिकट में घोटाला बताकर फ्री बस सेवा से वंचित करना चाहती है। सवाल यह है कि पिंक टिकट में घोटाला कैसे हो सकता है। डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त टिकट मिलता है।

दिल्ली को कर्ज में डूबो रही सरकार : देवेंद्र यादव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली को विकसित नहीं कर रही बल्कि कर्ज में डूबा शहर बना रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत दिल्ली सरकार ने 600 करोड़ रुपये के कर्ज का प्रस्ताव पर्यटन परियोजनाओं के लिए भेजा है जबकि झुग्गी-बस्तियों में आवास, साफ पानी और राशन जैसी बुनियादी जरूरतें अभी भी अधूरी हैं।

भारतीयता का मतलब नफरत की दीवार खड़ी करना : उदितराज

» संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता भड़के

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के भारतीयता वाले बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जात-पात, छुआछूत यहां है। भयंकर गरीबी यहां है। हिंदू-मुसलमान का रोज का झगड़ा है। जाति का नफरत है और दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है, मुंह से कुछ भी बोल दें। पहले अपने समाज को दुरुस्त करना होगा। उदित राज ने कहा, कि इनके लिए भारतीयता क्या है? जातियों में बांटना, नफरत की दीवार खड़ी करना। आज भी दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता छुआछूत आज भी है। राष्ट्रपति तक मंदिर में नहीं जा सकतीं। क्या है इनकी भारतीयता. एक भी कॉर्पोरेट हाउस में दलित पिछड़ा नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इनके भारतीयता का मतलब है कि 10-5 फीसदी लोग बाकी के लोगों का शोषण करें। बाकी के शूद्र बनकर उनकी सेवा करें। भारतीय समाज में जाति के अलावा है क्या?। बता दें मोहन भागवत ने मंगलवार (23 जुलाई) को लोगों से भारतीयता को आत्मसात करने और दुनिया को उन सभी समस्याओं का समाधान दिखाने का आह्वान किया, जिनका वह सामना कर रही है। इग्नू और अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली में भागवत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भौतिकवाद के कारण विश्व अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है और अब वह इनके उत्तर के लिए भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि पिछले 2,000 वर्षों में लोगों के जीवन में खुशी और संतोष लाने के लिए पश्चिमी विचारों पर आधारित सभी प्रयास विफल हो गए हैं। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में विज्ञान और आर्थिक क्षेत्र में हुई सभी प्रगतियों ने विलासिता की चीजें ला दीं और लोगों का जीवन आसान बना दिया, लेकिन दुखों का अंत नहीं कर सकीं। भागवत के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को भी अपने निशाने पर ले लिया है।

लोग देश छोड़कर भाग क्यों रहे

अगर भारतीयता समाधान होता तो लोग देश छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। 40 लाख लोग अमेरिका चले गए, कौन अमेरिकी, ब्रिटिश नागरिक यहां आकर रह रहा है।

लखनऊ के क्लब में बाउंसरों की दबंगई!

» बार में युवती से छेड़छाड़ विरोध पर मारपीट व जानलेवा हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के देर रात खुलने वाले अलग-अलग क्लबों में तैनात बाउंसरों की ओर से दबंगई और गुंडई से जुड़े अनेकों मामले सामने आते हैं। इन घटनाओं से जुड़ी जानकारियां सामने आने के बाद भी लखनऊ पुलिस ऐसे क्लब संचालकों पर कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आती है लेकिन अब राजधानी लखनऊ में ऐसे ही एक क्लब में बाउंसरों की ओर से की गई दबंगई व छेड़छाड़ से जुड़ा एक नया मामला सामने आया, जिसने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर किया जा रहे दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

दरअसल, लखनऊ के फीनिक्स पलासियो स्थित टॉनिक बार में बर्थडे पार्टी करने पहुंची एक युवती के साथ वहां पर तैनात बाउंसरों की ओर से छेड़छाड़ व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया।

इस मामले में पीड़िता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर बाउंसरों ने पहले तो मारपीट की और उसके बाद उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए जान से करने का प्रयास भी किया। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

शहर को सुंदर बनाने में कर्मचारी संघ भी करेगा काम

» कर्मचारियों की समस्याओं का होगा समाधान, महापौर ने दिया आश्वासन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आज महापौर द्वारा नगर निगम लखनऊ के सभी कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री को अपने कैंप कार्यालय में बुलाकर बैठक कर सभी को संबोधन किया महापौर द्वारा अपने संबोधन में कहा के देश में स्वच्छता के मामले में अपना लखनऊ शहर तृतीय स्थान पर आया है लखनऊ को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मान भी दिया गया है।

जिस हेतु हम सभी की बराबरी की भागीदारी रही आप सभी के सहयोग से ऐसा सम्भव हुआ जिस लिये आप सब धन्यवाद् के पात्र हैं इसी तरह हम सब मिल कर ऐसे ही काम करेंगे और प्रयास करेंगे की अपना शहर अगली बार नंबर एक पर आ जाये जिस हेतु हम सब मिल कर एक वृहद स्तर पर बड़ी जागरूपता रैली भी निकाल कर सभी को स्वच्छ्ता के प्रति और जागरूप करेंगे। इसी क्रम में नगर निगम कर्मचारी संघ,लखनऊ के अध्यक्ष आनन्द वर्मा और महामंत्री शमील एखलाक द्वारा महापौर को आश्वासन दिया गया की नगर निगम लखनऊ का प्रत्येक कर्मचारी लखनऊ को देश में नंबर एक लाने के लिये अपना पूर्ण सहयोग और योगदान देगा और नागरिको को स्वच्छता हेतु प्रेरित करेगा।

कर्मचारी संघ ने दिया 30 सूत्रीय मांग-पत्र का ज्ञापन

नगर निगम कर्मचारी संघ, लखनऊ के अध्यक्ष आनन्द वर्मा एवम् महामंत्री शमील एखलाक द्वारा महापौर को सफाई, आर आर विभाग, उद्यान विभाग, मार्ग प्रकाश, अभियंत्रण, कैटिल कैचिंग, लिपिक संवर्ग, राजस्व संवर्ग के कर्मचारियों की लम्बित 30 सूत्रीय मांग-पत्र का ज्ञापन दिया।

भारत ने इंग्लैंड से वनडे सीरीज 2-1 से जीती

» तीसरे मैच में 13 रन से हराया, हरमनप्रीत चमकीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेस्टर-ली-स्ट्रीट। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने अंतिम वनडे 13 रन से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से पांच मैचों की टी20 सीरीज में हराया था। रिवरसाइड ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम ने पांच विकेट पर 318 रन बनाए।

जवाब में इंग्लैंड की महिला टीम 49.5 ओवर में 305 रन पर सिमट गई। इससे पहले दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता था। प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने टीम को इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 64 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद मंधाना और हरलीन देओल 45-45 रनों की पारियां खेलकर पवेलियन लौट गईं। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 84 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 102 रन बनाए और भारत का स्कोर 300 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 50 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान ऋचा घोष 38 और राधा यादव दो रन बनाकर नाबाद रहीं। वहीं 319 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को शुरुआत अच्छी नहीं रही। इसके बाद एम्मा लैंब और कप्तान नैट सिवर ब्रंट के बीच तीसरे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी हुई। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका।

क्रिकेट में अब नहीं दिखेगा रसेल पावर

जमैका। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 37 साल के इस ऑलराउंडर ने करियर के आखिरी दो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टी20 के रूप में खेले। इस सीरीज में हालांकि, वह कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन अब यह तो तय है कि अब उनकी दमदार हिटिंग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दिखेगी। इसकी वजह से उन्हें कई नाम भी मिले...जैसे रसेल मसल, रसेल पावर...इत्यादि। रसेल ने अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच में 15 गेंद में दो चौके और चार छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने एक ओवर गेंदबाजी भी की और 16 रन लुटाए।

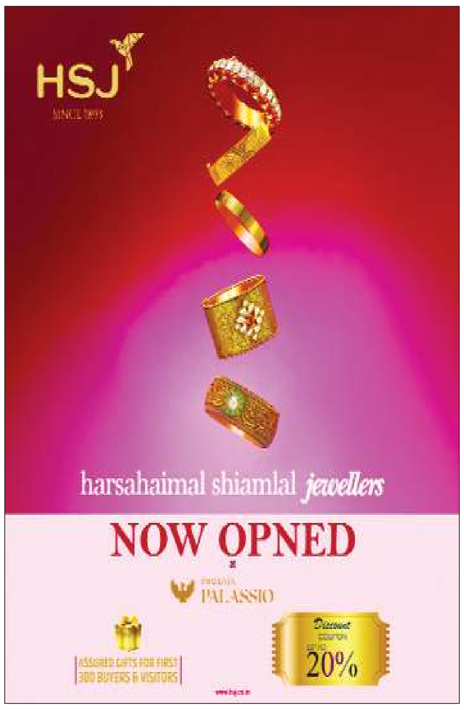

बाप शब्द पर बिहार विधानसभा में कोहराम

सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा, राजद नेता भाई वीरेंद्र बोले- माफी नहीं मांगूंगा, डिप्टी सीएम का पलटवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज सत्र का तीसरा दिन था और कार्यवाही भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन मुद्दे पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र के एक बयान पर हंगामा और बढ़ गया।

दरअसल, तेजस्वी यादव सदन में बोल रहे थे। वही सरकार को निशाना साध रहे थे। हालांकि, इस दौरान सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य बीच में शोर करने लगे। इसी बात पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है। विपक्ष को भी यहां पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। भाई वीरेंद्र के इतना कहते ही सदन का माहौल पूरी तरह से गरम हो गया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष, दोनों के सदस्य आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर ही दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, "इस सत्र के केवल तीन दिन ही बचे हैं। जो कुछ भी कहना है, वो चुनाव के समय कहिएगा।" यादव राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बयान दे रहे थे, जिस पर सदन के नेता ने आपत्ति जताई। इसे लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।वहीं, मीडिया से बात करते हुए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैंने जो भी कहा है, मैं उस पर कायम हूँ। मैंने कहा है कि सदन किसी की जागीर नहीं है। मैंने जो कहा, उसमें ग़लत क्या था? ये संसदीय भाषा है। इसके बाद मंत्री गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ? मैंने क्या ग़लत किया है?... क्या विजय सिन्हा हमारे नेता हैं? क्या वो हमारे मालिक हैं? वो मेरे सामने पैदा हुए हैं।

तेजस्वी तुम अभी बच्चे हो अभी नहीं समझोगे : नीतीश

सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी से पूछा कि राजद ने मुसलमानों के लिए आज तक क्या किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए मैंने काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की बात करें तो हम पहले भी महिला आरक्षण दिया था और आज भी हमने महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दे रहे हैं। नीतीश ने तेजस्वी से कहा कि तुम अभी बच्चे हो अभी नहीं समझोगे।

कैमरे में बने रहने के लिए बकवास करते हैं डेप्युटी सीएम: तेजस्वी

बिहार विधानसभा में बुधवार को हुए हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्तापक्ष और खासकर डेप्युटी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डेप्युटी सीएम को ये तक कह दिया कि उनको कुछ नहीं आता है केवल कैमरे पर बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष भाई वीरेंद्र के सदन किसी के बाप का नहीं वाले बयान का भी बचाव किया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्पीकर से बात करके उनसे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा कराने का अनुरोध किया गया था। सदन में जब हमें मौका मिला तो हम सर की टाइमिंग, डॉक्यूमेंट, बिहार से बाहर कमाने खाने गए लोगों पर बात रखी गई। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि करीब 55 लाख लोगों को अनुपस्थित पाया। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे।

मस्जिद में सपा की बैठक पर सियासी मचा बवाल

» भाजपा ने सपा मुखिया पर बोला हल्ला, अखिलेश बोले- भाजपा चाहती है लोग बंटे रहें

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नोएडा। समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में कथित तौर पर बैठक करने पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि अखिलेश ने मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया, जिसपर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जवाब दिया है।

अखिलेश यादव के जवाब पर यूपी की डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। दिल्ली में संसद मार्ग स्थित एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर हुई बैठक पर अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। भाजपा को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। भाजपा लोगों में दूरियां देखना चाहती है। भाजपा चाहती है कि लोग एकजुट न होकर बंटे रहें। हमारी सभी धर्मों में आस्था है। भाजपा को तकलीफ है तो हम क्या करें। भाजपा को आप सब जानते हैं, भाजपा का हथियार ही धर्म है। वहीं, अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर मस्जिद के अंदर बैठक करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि क्या अब हमें मंदिर और मस्जिद जाने के लिए भाजपा से लाइसेंस लेना होगा?।

वो हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं : पाठक

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर एक बैठक के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के राष्ट्रीय

अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं। भारतीय संविधान कहता है कि हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। पाठक ने अखिलेश यादव को समाजवादी न कहकर नमाजवादी कहा।

मस्जिद परिसर के अपमान किया गया : जमाल सिद्दीकी

अब दूसरी ओर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने संसद भवन के पास मस्जिद में 25 जुलाई को जुम्मे की नमाज़ के बाद दोपहर 1 बजे

बैठक की योजना बनाई थी। हालांकि उन्होंने इसे जुम्मे के दिन तक के लिए स्थगित कर दिया है। सिद्दीकी ने कहा कि वे जल्द ही मस्जिद प्रबंधन को पत्र लिखकर राजनीतिक बैठक की अनुमति मांगेंगे, जैसा कि अखिलेश यादव ने हाल में किया था। अनुमति मिलने पर वे अपनी टीम के साथ मस्जिद में बैठक करेंगे। पत्र को जल्द साझा करने की बात भी कही गई है। यही नहीं जमाल सिद्दीकी ने अखिलेश की बैठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मस्जिद की पहली मंजिल पर महिलाएं भी थीं, जिनके सिर नहीं ढके थे और उनके कपड़े मस्जिद की मर्यादा के अनुरूप नहीं थे।

लालू के परिवार पर आरोप तय करने का आदेश टला

» आईआरसीटीसी घोटाला मामला : दिल्ली कोर्ट केस 4 अगस्त को सुनेगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में आरोप तय करने का आदेश टाल दिया। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य और अन्य आरोपी हैं। यह मामला आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से स्पष्टीकरण माँगा और मामले को 5 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने जाँच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की दैनिक आधार पर

दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली। इस मामले में 14 आरोपी हैं। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह ने अधिवक्ता मनु मिश्रा के साथ सीबीआई की ओर से दलील दी कि आईआरसीटीसी के दो होटल रखरखाव ठेकों के आवंटन में आरोपियों की ओर से भ्रष्टाचार और साजिश रची गई थी।

सीबीआई ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। यह मामला उस दौर से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी, के रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के ज़रिए तीन एकड़ बेशकीमती ज़मीन मिली।

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई से सीजेआई गवई अलग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कैशकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की है।

रिपोर्ट में दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने की बात पुष्टि की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने खिलाफ आई रिपोर्ट और उन्हें पद से हटाने की चीफ जस्टिस की सिफारिश को चुनौती दी है। मामले में कुछ संवैधानिक सवाल हैं। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि इसके लिए विशेष बेंच बनानी पड़ेगी। मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि तत्कालीन चीफ जस्टिस ने मुझसे भी सलाह ली थी।

गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का पर्दाफाश, एसटीएफ ने की कार्रवाई

» पीएम-राष्ट्रपति के साथ फेक फोटो लगाकर बन बैठा नकली एंबेसडर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नोएडा। उत्तर प्रदेश की नोएडा एसटीएफ (एसटीएफ) ने गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया। पुलिस ने हर्ष वर्धन जैन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हर्ष वर्धन पर आरोप है कि वह खुद को कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों को ठग रहा था। वह हवाला के जरिए पैसे का लेन-देन भी करता था।

पुलिस के अनुसार, हर्ष वर्धन कविनगर में किराए के मकान में वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। वह खुद को वेस्ट आर्कटिक,सैबोंगा, पुओलिवा व लोडोनिया जैसे देशों का कॉन्सुल या एम्बेसडर बताता था। लोगों को झांसा देने के लिए, वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपनी फोटोशॉप की हुई तस्वीरें दिखाता था। पुलिस का कहना है कि हर्ष वर्धन का मुख्य काम कंपनियों और लोगों को विदेश में काम

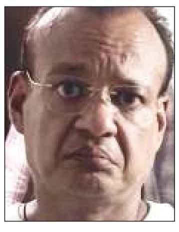

दिलाने के नाम पर दलाली करना था। वह शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला रैकेट भी चला रहा था। जांच में पता चला है कि हर्ष वर्धन पहले चंद्रास्वामी और अदनान खगोशी (अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर) के संपर्क में भी था। 2011 में उसके पास से एक अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था, जिसके लिए कविनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने हर्ष वर्धन के पास से कई चीजें बरामद की हैं। इनमें डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी चार गाड़ियां, माइक्रोनेशन देशों के 12 डिप्लोमैटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे फर्जी दस्तावेज, दो फर्जी पैनकार्ड, विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 44,70000 रुपए नकद और कई देशों की विदेशी मुद्रा शामिल हैं। इसके अलावा, कई कंपनियों के दस्तावेज और 18 डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा** द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **महाराष्ट्र कार्यालय**:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। **संपादक** - संजय शर्मा, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website:** www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।